an>

Title: Regarding the proposal of WTO to abolish subsidy and MSP provided to the farmers.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं इस हाउस में उठाना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से समाचार-पत्रों में खबरें आ रही हैं कि जो नैरोबी में 15 से 18 दिसम्बर तक डब्ल्यू.टी. की ओर से मंत्री स्तर की कांफ्रेंस होने जा रही है, उसमें बहुत चिंताजनक खबरें आई हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री, पंजाब ने भी माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है, जो शर्तें वे विकसित देश विकासशील देशों पर लगाना चाहते हैं, जैसे पब्लिक स्टॉक सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, उससे तो हमारा फूड सिक्योरिटी का संकल्प खत्म हो जाएगा। जैसे हम आटा, दाल सस्ता देते हैं। ऐसे ही एमएसपी को वे किसानों के लिए सब्सिडी के तौर पर ले रहे हैं और शर्त लगाई जा रही है कि वर्ष 1986 तक 1998 तक का 10 परसेंट से ज्यादा इनक्रीज नहीं हो पाएगा। इससे किसान की उपज का मूल्य बढ़ने की जगह कम हो जाएगा और यह किसान के लिए खुदकुशी की बात हो जाएगी।

तीसरी शर्त यह रखी जा रही है कि स्पेशल सिक्योरिटी अपने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए विकासशील देश लगा देते हैं, वे खत्म करना चाहते हैं। जो विकसित देश हैं, वे दादागिरी दिखाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि 15 से 18 दिसम्बर को जो कांफ्रेंस हो रही है, भारत सरकार विकसित देशों की शर्तों के आगे न झुके और हमारा हाउस सर्वसम्मति से सरकार से निवेदन करे कि जो शर्तें लगाई जा रही हैं, उन्हें भारत सरकार किसी भी रूप में न माने तो किसान बच पाएगा, नहीं तो इसके बहुत खतरनाक नतीजे सामने आने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष :

श्री प्रहलाद सिंह पटेल,

श्री पी.पी. चौधरी,

डॉ. वीरेन्द्र कुमार

श्री दुष्यंत चौटाला,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।